स्थापना : 1997 संपर्क : 09869256875

प्रत्येक महीने की 1ली और 16वीं तारीख एवं दिन को प्रकाशित

• Website : www.railsamachar.com
• Website : www.railsamacharenglish.com
• Email : railwaysamachar@gmail.com

परिपूर्ण रेलवे समाचार

रेलवे का दोस्त, यात्रियों का साथी

■ वर्ष -14 ■ अंक - 328 ■ कल्याण (मुंबई), ■ 1 से 15 जनवरी 2016 ■ पेज - 8 ■ मूल्य 5 रु.

बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण

सुरेश त्रिपाठी

अपने पास कोई अधिकार न रखने वाले रेलमंत्री को गुमराह कर रहे हैं रेलवे बोर्ड के अधिकारी

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से रेल बजट में जो घोषणाएं उन्होंने की थीं, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए बिंदुवार विभाजित कर लिया गया है. साथ ही सभी परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित नजर रखी जा रही है. उन्हें प्रधानमंत्री को यह सूचित करते हुए अत्यंत खुशी हुई है कि बजट की घोषणाओं में से 103 घोषणाएं अमल में लाई जा चुकी हैं. जबकि प्रभु ने पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए लोकसभा में 16 मार्च, 2015 को स्वीकार किया था कि पिछले वर्ष यानी 2014 की समाप्ति तक रेलवे की 930 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा बना हुआ था, जिसे अनधिकृत रूप से स्थानीय दबंग लोग कब्जाए हुए हैं. हालांकि इस विषय पर सरकार से भी ज्यादा विश्वसनीय निजी तौर पर कुछ जागरूक लोगों से प्राप्त आंकड़ा यह है कि वर्तमान में पूरे देश में रेलवे की 1999 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है. जबकि हाईटेक रेलमंत्री सुरेश प्रभु इस पर खामोश हैं. सरकारी बाबू लोग अपनी खाल बचाने के लिए नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के आंकड़े इस अंदाज में पेशप्रस्तुत करते हैं जैसे वह नगण्य-सी बात हो. परंतु जब उन्हें अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना होता है, तब उन्हीं नगण्य से आंकड़ों को पहाड़ बना दिया जाता है. रेल मंत्रालय के बाबुओं ने रेलमंत्री को रेलवे की जमीन का हिसाब दिया है कि चूंकि भारतीय रेल के पास 4.58 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है, इसलिए इस पर अतिक्रमण का आंकड़ा (930 हेक्टेयर) मात्र 0.20 प्रतिशत ही है. जबकि जागरूक लोगों के अनुसार यह आंकड़ा 0.50 प्रतिशत से भी ऊपर है, फिर भी रेलवे के बाबुओं को यह बेहद मामूली लगता है. रेल मंत्रालय के बाबुओं द्वारा उपलब्ध कराया गया उपरोक्त आंकड़ा भी रेलमंत्री ने लोकसभा को बताया था कि पूरे देश में रेलवे की लगभग 0.47 प्रतिशत जमीन रेल पटरियों के अगल-बगल संकरी पट्टियों के रूप में खाली पड़ी रहती है, जो पटरियों, पुलों और अन्य ढांचागत मरम्मत के काम आती है. यानी यह रेलवे की वह जमीन है, जो रेलवे से यात्रा के दौरान लोग नदियां, जंगल, पहाड़, अपने शहर और गांव फलांगते हुए पूरे देश में पार करते जाते हैं. दोनों आंकड़ों की तुलना की जाए, तो स्पष्ट होता है कि जितनी जगह पूरे देश में रेलवे की सेहत का मर्सिया पढ़ने शेष पेज 4 पर...

नहीं हो पाई समय पर मेंबर इलेक्ट्रिकल की नियुक्ति

- मेंबर स्टाफ को सौंपा गया मेंबर इलेक्ट्रिकल का अतिरिक्त चार्ज
- उपयुक्त चयन न होने पर चार साल में 10 हजार किमी. ट्रैक के विद्युतीकरण का लक्ष्य पाना मुश्किल

सुरेश त्रिपाठी

भारतीय रेल की यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि जो काम समय पर और वरीयता क्रम में होना चाहिए, वही नहीं होता, इसके अलावा बाकी सब कुछ होता रहता है. यहां तक कि जो काम चल रहा होता है, उसे भी दरकिनार करके उसकी जगह कोई दूसरा काम शुरू कर दिया जाता है. उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर को मेंबर इलेक्ट्रिकल के पद से नवीन टंडन और एडीशनल मेंबर, स्टाफ के पद से मोहम्मद अख्तर सेवानिवृत्त हो गए. यह तारीख सभी को पहले से पता थी. इसके अनुसार नए मेंबर इलेक्ट्रिकल और नए एडीशनल मेंबर स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया कम से कम महीने भर पहले शुरू हो जानी चाहिए थी. जबकि एडीशनल मेंबर स्टाफ के लिए कोई विवाद अथवा चयन की भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसके लिए भी फिलहाल आनद माथुर शेष पेज 7 पर...

वड़ोदरा मंडल के स्टेशनों का नाम उर्दू में लिखे जाने का भारी विरोध

- गुजरात सरकार के आदेश पर लिखे गए उर्दू में नाम, रेलवे के निर्देश का पता नहीं

वड़ोदरा : पश्चिम रेलवे के वड़ोदरा मंडल के भरुच एवं नबीपुर जैसे कई रेलवे स्टेशनों पर चौथी भाषा (उर्दू) में स्टेशनों के नाम लिखे देखकर हाल ही में कई यात्रियों को भारी अचम्भा हुआ. उन्होंने इस बारे में 'रेलवे समाचार' को फोन करके पूछा कि क्या ऐसा कोई दिशा-निर्देश रेलवे बोर्ड से जारी किया गया है? इस बारे में उनका यह भी कहना था कि यदि एक वर्ग विशेष शेष पेज 7 पर...

लंबे समय से संवेदनशील पदों पर बैठे रेलकर्मियों को हटाने में नाकाम रेल प्रशासन

दिल्ली : रेलवे बोर्ड द्वारा 17 दिसंबर 2015 को एक नोटिफिकेशन (संख्या ई(एनजी)1-2009/टीआर/7, आरबीई 158/2015) जारी करके सभी जोनल रेलों के महाप्रबंधकों (कार्मिक) को यह आदेश दिया गया है कि लंबे समय से संवेदनशील पदों पर पदस्थापित रेलकर्मियों को न सिर्फ उनके वर्तमान पदों से फौरन हटाया जाए, बल्कि ऐसे सभी पदों पर पीरियोडिकल ट्रांसफर को सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन

- रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश पर जोनल रेलों द्वारा नहीं किया जा रहा है अमल
- रेलवे में नीचे से ऊपर तक व्याप्त भारी भ्रष्टाचार का भी है यही सबसे बड़ा कारण

में यह भी कहा गया है कि जो रेलकर्मी लगातार पब्लिक, कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स के संपर्क में आते हैं, उन्हें भी प्रत्येक चार वर्ष में अन्यत्र शिफ्ट किया जाना चाहिए. रेलवे बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन के साथ ऐसे सभी पदों की सूची में जारी की है.

परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सीवीसी के साथ तय हुई ऐसे सभी पदों की यह सूची रेलवे बोर्ड विजिलेंस द्वारा पांच साल पहले ही सभी जोनल रेलों को जारी की जा चुकी है. तथापि आज तक किसी भी जोनल रेलवे द्वारा इस पर वस्तुतः अमल नहीं किया गया है. रेलवे बोर्ड का उपरोक्त शेष पेज 7 पर...

आरपीएफ का 23वां अधिवेशन मुंबई में

मुंबई : ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन (एआईआरपीएफए) का 23वां वार्षिक अधिवेशन 7 से 9 जनवरी को मुंबई सेंट्रल स्थित सीमेंट चाल, आरपीएफ लाइन मैदान में होने जा रहा है. इस अधिवेशन में रेलमंत्री सुरेश प्रभु सहित कई स्थानीय सांसद, जन-प्रतिनिधि और मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के भी भाग लेने की उम्मीद है. इस अवसर पर आरपीएफ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री यू. एस. झा ने पहली बार आरपीएफ कर्मियों से सम्बंधित कुल 36 महत्वपूर्ण मांगों को रेल प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया है.

सातवें वेतन आयोग से रेलवे पर पड़ेगा 32 हजार करोड़ का बोझ

पर्याप्त बजटरी सहयोग के आभाव में बढ़ सकता है यात्री और माल भाड़ा

दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को 1 जनवरी 2016 से ही लागू किए जाने पर एक बार फिर अपनी सहमति जताई है. परंतु इसके लागू होने से रेलवे पर 32000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है. रेलवे के लिए अकेले हर साल इतनी बड़ी राशि का प्रबंध करना मुश्किल हो सकता है. रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की चिंता सता रही है कि यदि केंद्र सरकार ने पर्याप्त बजटरी सहयोग नहीं दिया, तब रेलवे के लिए अकेले यह बोझ वहन कर पाना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा. इसके विकल्प के तौर पर रेल मंत्रालय यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ा सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव रेल यात्रियों और मालवाहकों पर पड़ेगा. जबकि अप्रत्यक्ष रूप से बाजार में चीजें महंगी हो जाएंगी.

अधिकारियों का कहना है कि पहले से ही आर्थिक कठिनाई से गुजर रही रेलवे के लिए हर साल इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करना एक बड़ी समस्या होगी. रेलवे के लिए अकेले 32 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त इंतजाम करना आसान नहीं है. शेष पेज 7 पर...

डी. सी. शर्मा के साथ अन्याय तो हुआ है..

- शर्मा को उनका वाजिब हक और प्रमोशन दिया जाना चाहिए
- पूर्व सीआरबी की नियुक्ति के पूरे प्रकरण की गहराई से जांच होनी चाहिए

'रेलवे समाचार' द्वारा 18 दिसंबर को 'हे प्रभु, डी. सी. शर्मा के मामले में अरविंद केजरीवाल को क्या मुंह दिखाओगे ! डी. सी. शर्मा को ओएसडी/जम्मू के बाद अब बनाया जा रहा है रेल मंत्रालय में ईडी/हेरिटेज?' शीर्षक से प्रकाशित खबर पर कई वरिष्ठ मैकेनिकल एवं अन्य रेल अधिकारियों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है. इन अधिकारियों का कहना है कि श्री शर्मा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी. तथापि, उन्हें डीआरएम नहीं बनने दिया गया है. यह रेल प्रशासन और रेलवे बोर्ड की बहुत बड़ी और अक्षम्य गलती है.

इन अधिकारियों का कहना है कि यदि श्री शर्मा की कोई गलती थी, तो रेलवे बोर्ड आज तक उन्हें चार्जशीट क्यों नहीं दे पाया है? उन्होंने कहा कि यदि रेलवे बोर्ड ने गलती मानकर ही सीवीसी से एडवाइस मांगी थी और जब सीवीसी ने बिना अपने दिमाग का कोई इस्तेमाल किए श्री शर्मा को मेजर पेनाल्टी और आर. एस. विर्दी को माइनर पेनाल्टी की एडवाइस कर दी थी, तो रेलवे बोर्ड ने यह चार्जशीटें आज तक सर्व क्यों नहीं की हैं? जबकि श्री विर्दी बिना चार्जशीट सर्व हुए ही जीएम पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. यदि वह दोषी थे, तो रेलवे बोर्ड ने सीवीसी की एडवाइस लेने के बाद तत्काल उन्हें चार्जशीट सर्व क्यों नहीं की थी?

इन अधिकारियों का कहना है कि इसका मतलब यह है कि तत्कालीन मेंबर मैकेनिकल और मंत्री ने श्री विर्दी को सीआरबी नहीं बनने देने के लिए यह सारा फर्जीवाड़ा किया था. जो कि पूर्व मेंबर मैकेनिकल एस. दसरथी द्वारा लिखित में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बाद वास्तव में फर्जीवाड़ा ही साबित हुआ था. उनका यह भी कहना है कि इसके लिए तत्कालीन सीवीसी भी समान रूप से जिम्मेदार और दोषी हैं, जिन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करके इस तमाम फर्जीवाड़े में तत्कालीन मेंबर मैकेनिकल का सहयोग किया था. उनका कहना है कि पूर्व सीआरबी की नियुक्ति के पूरे प्रकरण की गहराई से जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए. मगर उससे पहले श्री शर्मा को उनका वाजिब हक और प्रमोशन दिया जाना चाहिए.

उत्तर रेलवे में की गई डी. सी. शर्मा की पोस्टिंग

फिलहाल ओएसडी/जम्मू के पद पर कार्यरत रहे डी. सी. शर्मा को ईडी/हेरिटेज की पोस्टिंग न देकर उन्हें उत्तर रेलवे कैडर में पदस्थ कर दिया गया है. तत्संबंधी आदेश रेलवे बोर्ड से 23 दिसंबर को जारी किया गया है. श्री शर्मा की पोस्टिंग ए. के. राना की जगह हुई है, जिन्हें एडीआरएम/जम्मू बनाया गया है. जबकि 28 दिसंबर को जारी एक अन्य आदेश के अनुसार वर्तमान ईडी/हेरिटेज मनु गोयल का उक्त पद पर 28 दिसंबर को ही पूरे हुए कार्यकाल के बाद उनका ट्रांसफर कॉम्पोव कैडर में किया गया है.

आरपीएफ थाना, पनवेल का सराहनीय कार्य. मंगलवार, 29 दिसंबर को हरियाणा राज्य स्केटिंग संगठन के 45 स्कूली बच्चों की एक टीम गाड़ी संख्या 12217 से दिल्ली जाने हेतु जब पनवेल रेलवे स्टेशन पहुंची, तब उसे पता चला कि उक्त गाड़ी 5 घंटे लेट है. टीम के पास पर्याप्त भोजन सामग्री नहीं थी. ऐसे में टीम के कोच उमेश सैनी ने आरपीएफ थाना, पनवेल को संपर्क करके समुचित कीमत पर बच्चों को दोपहर का खाना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इसके बाद आरपीएफ के सभी सदस्यों ने मिलकर पनवेल स्टेशन के कैटरिंग कांट्रेक्टर से अनुरोध करके आरपीएफ पोस्ट के सामने ही बैठाकर पूरी टीम को खाना खिलाया.

एआईआरपीएफए/दपूरे की जोनल कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

कोलकाता : ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, दक्षिण पूर्व रेलवे की जोनल कार्यकारिणी की बैठक गार्डन रीच, कोलकाता में 28 दिसंबर को संपन्न हुई. बैठक में तय एजेंडा के अनुसार मुद्दों पर चर्चा की गई. तत्पश्चात एसोसिएशन के महामंत्री प्रमोद कुमार ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ महाप्रबंधक, द.पू.रे. ए. के. गोयल से उनके कार्यालय में मुलाकात की. उनकी मांग पर महाप्रबंधक श्री गोयल ने जोनल स्तर की पीएनएम बैठक जल्दी ही कराए जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की. इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने सीएससी/आईजी/आरपीएफ से भेंट कर उनके साथ आरपीएफ कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा की. सीएससी के साथ दिल्ली एवं कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में आरपीएफ रूल 78.1 के तहत एंसिलरी स्टाफ के फिक्शेसन एवं कैडर चेंज करने को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई. सीएससी ने इस संदर्भ में प्रक्रिया को तेज किए जाने का आश्वासन दिया है. इसके अलावा सीएससी के साथ स्टाफ क्वार्टर और वर्दी के कपड़े तथा अनुकम्पा नियुक्ति के कुछ मामलों पर लेकर भी चर्चा हुई. सत्फ की पदोन्नति एवं एमएसीपी पर भी सीएससी ने सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया.

अखिल भारतीय रे.सु.ब. संगठन, भुसावल मंडल, मध्य रेलवे की वार्षिक सर्वसाधारण बैठक 30 दिसंबर को भुसावल में संपन्न हुई. इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य रेलवे के महामंत्री एस. आर. रेड्डी सहित मुंबई से डी. सी. पांडेय, सोलापुर से राजेश मिश्रा, विक्रम सिंह चाहर और पुणे एवं नागपुर मंडलों के भी पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में नई मंडल कार्यकारिणी का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रेड्डी की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें आईपीएफ वी. के. लांजीवार, अध्यक्ष, समाधान वाहुलकर, कार्याध्यक्ष, ए. एस. गायकवाड़, उपाध्यक्ष, रोशन सिंह, मंडल सचिव, के. वी. सिंह, संयुक्त सचिव, प्रशांत गवई, सहायक सचिव, के. बी. सिंह, संगठन सचिव, दिलीप बारी, कार्यालय सचिव और नूर मोहम्मद को कोषाध्यक्ष चुना गया.

'रेलवे नियामक प्राधिकरण' के बजाय अब 'रेलवे विकास प्राधिकरण'

दिल्ली : रेलमंत्री सुरेश प्रभु अब 'रेलवे नियामक प्राधिकरण' (रेलवे रेग्युलेटरी अथॉरिटी) का नाम बदलकर 'रेलवे विकास प्राधिकरण' (रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी) करने जा रहे हैं. उन्होंने हाल ही में इसके नाम में परिवर्तन का एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा है. उन्होंने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह प्राधिकरण रेलवे से जुड़ी विभिन्न तरह की विकास सम्बंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन करने के साथ ही माल भाड़ा और यात्री किराया भी तय करेगा. रेलमंत्री ने कहा कि एक दशक से अधिक समय से रेलवे रिफॉर्म से जुड़ी अधिकांश समितियों ने एक स्वतंत्र रेलवे रेग युलेटर बनाने की सिफारिश की है. अब इसे वास्तविक स्वरूप देने का समय आ गया है. रेलमंत्री श्री प्रभु के अनुसार इस प्राधिकरण के तहत रेलवे के विकास कार्यों सहित पैसेंजर और फ्रेट टैरिफ की निगरानी के लिए उचित ढांचा बनाने, पीपीपी प्रोजेक्ट्स तय करने और रेलवे की कार्यकुशलता सुनिश्चित करने जैसे काम भी शामिल होंगे. रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 'रेलवे रेग्युलेटरी अथॉरिटी' का नाम बदलकर 'रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी' करने का प्रस्ताव किया गया है. अधिकारी ने बताया कि रेलवे में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के प्राधिकरण की स्थापना आवश्यक हो गई है. इससे रेलवे के कार्यों में पारदर्शिता आएगी. अधिकारी का कहना था कि इस मामले में रेलवे पब्लिक समेत सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मंगाएगी. यह सुझाव इस प्राधिकरण के निर्माण से लेकर इसके क्रियाकलापों के विस्तार आदि सभी गतिविधियों से सम्बंधित होंगे. अधिकारी ने कहा कि 'रेलवे विकास प्राधिकरण' का डॉफ्ट बनकर तैयार है और सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मंगाने के लिए इसे जल्दी ही सबके सामने लाया जाएगा. एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि इस प्रकार के प्राधिकरण के बनने से एक बात तो तय है कि रेलवे के यात्री एवं माल भाड़े को समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा और यह कार्य राजनीतिक पार्टियों के रहमोकरम पर निर्भर नहीं रह जाएगा. इस अधिकारी का यह भी कहना था कि यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर इस 'अथॉरिटी' या रेग्युलेटरी' का गठन अब तक इसलिए अटका हुआ था, क्योंकि रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य इसमें अपने-अपने कैडर का भी प्रतिनिधित्व चाह रहे हैं. जबकि यह काम विशेष रूप से सिर्फ ट्रैफिक कैडर का ही है.

विदेशी निवेश से होगा भारतीय रेल के कारखानों का आधुनिकीकरण

दिल्ली : रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए जापान और कोरिया सहित कई देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके साथ ही भारतीय रेल की 16 जोनल रेलों के 29 रेलवे कारखानों (वर्कशॉप्स) का आधुनिकीकरण किए जाने के विभिन्न कार्यों को मंजूरी दी गई है. शीत सत्र के दौरान यह जानकारी रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में दी है. लोकसभा में सांसदों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे रोलिंग स्टाक वर्कशॉप के आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने पर काम कर रही है. इसमें रोबोटिक वेल्डिंग मशीन, लेजर कटिंग और वेल्डिंग आदि शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि आधुनिक इस्पात आधारित वैगन, कोच का निर्माण तथा मरम्मत कार्य के लिए रेलवे वर्कशॉप्स को आधुनिक बनाने के लिए उपकरणों को शामिल करने की पहल की गई है. रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे के आधुनिकरण के लिए जापान, कोरिया सहित कई देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जा रहा है. जापान के साथ हाल ही में सहयोग केवल बुलेट ट्रेनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि जापान में सबसे कम रेल दुर्घटनाएं होती हैं. इसी तरह से कोरिया के साथ भी रेलवे के क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है.

संसद में रेलमंत्री के उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण के नाम पर रेलवे की लगभग सभी उत्पादन इकाईयों (पीयू) सहित मरम्मत एवं रख-रखाव कारखाने (वर्कशॉप्स) का भी निजीकरण होने जा रहा है. उल्लेखनीय है कि वैसे भी इन रेलवे वर्कशॉप्स में जहां कर्मचारियों की संख्या लगातार घटाई जा रही है, वहीं यहां का अब ज्यादातर कामकाज अभी ही निजी फर्मों को दे दिया गया है. यहां अब कोचों और इंजनों की पीरियोडिकल ओवर हॉलिंग (पीओएच) सहित रंगाई-पुताई और मरम्मत भी निजी फर्मों द्वारा ही की जा रही है. भ्रष्टाचार की हद यह है कि निजी फर्मों का यह काम भी ज्यादातर रेलवे वर्कशॉप्स के कर्मचारी ही कर रहे हैं, जिनको निजी ठेकेदार द्वारा अलग से कुछ भुगतान कर दिया जाता है. जबकि ज्यादातर कर्मचारी 11-12 बजे के बाद वर्कशॉप्स से नदारत पाए जाते हैं अथवा अधिकारियों के घरों पर उनके निजी काम-धंधे में लगे होते हैं.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में

रेलकर्मियों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

दिल्ली : भारतीय रेल पर मान्यताप्राप्त ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) एवं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) - से जुड़े सभी जोनल संगठनों ने बुधवार, 30 दिसंबर को सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और सातवें वेतन आयोग की निराशाजनक सिफारिशों तथा रेलवे के निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया. रेलकर्मियों ने कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के सामने धरना-प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया. इस मौके पर उनकी मांगें मानने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर कोसा तथा मांगों के समर्थन में 8 मार्च को हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी.

मीडिया को संबोधित करते हुए एआईआरएफ के महामंत्री कॉम. शिवगोपाल मिश्रा. उनके साथ है डब्ल्यूआरईयू के महामंत्री कॉम. जे. आर. भोसले और एनडब्ल्यूआरईयू के महामंत्री कॉम. मुकेश माथुर.

सातवें वेतन आयोग की निराशाजनक एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों तथा रेलवे के निजीकरण के विरोध में स्टेट जॉइंट कौंसिल ऑफ एक्शन के आह्वान पर एआईआरएफ से संलग्न संस्थाओ ने पूरे देश में 30 दिसंबर को धरना-प्रदर्शन किया.

एआईआरएफ के महामंत्री कॉम. शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलकर्मियों ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों और मंडल एवं जोनल मुख्यालयों पर धरना दिया. रेल कर्मचारी देश में 7वें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों को लागू करने, नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, रेलवे के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर लंबे समय से शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है. इससे रेल कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त हो रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यदि 7वें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया, तो रेल कर्मचारी मांगों के समर्थन में 8 मार्च को हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे.

उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस धरना-प्रदर्शन में लाखों रेलकर्मियों ने भाग लिया. इस देशव्यापी धरना-प्रदर्शन में रेल सनाग्थानो से जुड़े सभी कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग की निराशाजनक और प्रतिकूल सिफारिशों, एफडीआई, निजीकरण, नई पेंशन नीति के विरोध में रेलमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस धरना-प्रदर्शन में एआईआरएफ, एनएफआईआर के अलावा कंफडरेशन, एनएफपीआई, एआईडीईएफ के कर्मचारियों ने भी भाग लिया.

डब्ल्यूआरईयू की जोनल टेक्निकल स्टाफ कांफ्रेंस संपन्न

वड़ोदरा : वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन (डब्ल्यूआरईयू) द्वारा प्रतापनगर, वड़ोदरा में तीन दिवसीय 'जोनल टेक्निकल स्टाफ कांफ्रेंस' का आयोजन किया गया. कांफ्रेंस का शुरुआत डब्ल्यूआरईयू के महामंत्री कॉम. जे. आर. भोसले ने दीप प्रज्वलित करके किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता डब्ल्यूआरईयू के अध्यक्ष कॉम. आर. सी. शर्मा ने की. इस अवसर पर विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक, वड़ोदरा तथा अन्य मंडल अधिकारी भी उपस्थित थे. कांफ्रेंस में पहले दिन 29 दिसंबर को सभी टेक्निकल स्टाफ ने अपनी समस्याएं रखी तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया. इसी प्रकार 30 दिसंबर को इंजीनियरिंग विभाग और 31 दिसंबर को ऑपरेटिंग विभाग के तकनीकी कर्मचारी अपनी अपनी मांगों और समस्याओं को प्रस्तुत किया. इसके अलावा कांफ्रेंस में चर्चा का मुख्य मुद्दा सातवें वेतन आयोग द्वारा टेक्निकल स्टाफ के साथ किया गया अन्याय रहा.

सीआरएमएस की लोको रनिंग ब्रांच के अध्यक्ष पर विवेक शिशौदिया का चयन

कल्याण : सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (सीआरएमएस) के अध्यक्ष डॉ. आर. पी. भटनागर की उपस्थिति में 26 दिसंबर को सीआरएमएस मुंबई मंडल की लोको रनिंग ब्रांच का चुनाव रनिंग शाखा कार्यालय, कल्याण में संपन्न हुआ. इस मौके पर सीआरएमएस के महामंत्री प्रवीन बाजपेई, सयुंक्त महामंत्री अशोक चंगरानी, कोषाध्यक्ष रामगोपाल निम्बालकर, उपाध्यक्ष अमित भटनागर आदि सहित मुख्यालय एवं मंडल के सभी प्रमुख पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में उपस्थित रनिंग स्टाफ उपस्थित था. इस अवसर पर हुए रनिंग शाखा पदाधिकारियों के चुनाव में कुल 49 पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चयन हुआ. प्रमुख पदाधिकारियों में अध्यक्ष - विवेक शिशौदिया, कार्याध्यक्ष - आशीष देशमुख, उपाध्यक्ष - सुरेंद्र शर्मा, बी. एस. मीना, बी. पी. सिंह, गजेंद्र सिंह, शरद रणखम्भे, सचिव - अनिल दुबे और सह-सचिव पद पर बी. डी. ओझा, डी. एन. सिंह, मतलूब सिद्धीकी, गुल अडवानी एवं ओंकार नाथ गुप्ता का निर्विरोध चयन हुआ. शाखा के सलाहकार के रूप में अशोक चंगरानी को नामित किया गया है. इसके अलावा कार्यकारिणी के 25 सदस्यों का भी चयन किया गया. सभी चयनित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को डॉ. भटनागर एवं श्री बाजपेई ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए मजबूती के साथ काम करने को कहा.

रेलवे की वर्तमान सेहत सुधारने के बजाय बुलेट ट्रेन दौड़ाने में लगी केंद्र सरकार

वड़ोदरा : केंद्र सरकार मुंबई से अहमदाबाद के बीच 98 हजार करोड़ रुपए की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना रही है, लेकिन भारतीय रेल की वर्तमान स्थिति सुधारने में उसकी रुचि नहीं है. बुलेट ट्रेन में रोज केवल कुछ सौ या हजार लोग ही यात्रा करेंगे, लेकिन भारतीय रेल रोजाना ढ़ाई करोड़ से ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. इसकी सेहत सुधारने की कोई फिक्र केंद्र सरकार को नहीं हो रही है. रेलवे स्टेशन परिसर, महू में मंगलवार, 29 दिसंबर को पश्चिम रेलवे मजदूर संघ (डब्ल्यूआरएमएस) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह बात डब्ल्यूआरएमएस के महामंत्री और एनएफआईआर के उपाध्यक्ष जे. जी. माहूरकर ने कही.

उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारी जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उस हिसाब से उन्हें वेतन नहीं मिलता है. जोखिमपूर्ण कार्यों के समय कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होती है. इसके बावजूद रेलकर्मी विषम परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी करता है. उन्होंने कहा कि रेलवे के निचले कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है, जबकि वही सबसे अधिक मेहनत करते हैं. श्री माहूरकर के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में डब्ल्यूआरएमएस के अध्यक्ष शरीफ खान पठान, जसविंदर सिंह, वी. के. गर्ग, कैलाश दत्त पांडेय, एस. सी. खटवानी आदि गणमान्य उपस्थित थे. कार्यक्रम में पूर्व मंडल मंत्री श्री खटवानी को विदाई दी गई. बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने श्री माहूरकर का स्वागत किया.

जोखिमपूर्ण कार्यों में रेलकर्मियों की सुरक्षा-संरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता रेल प्रशासन : जे. जी. माहुरकर

इस अवसर पर श्री माहूरकर ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में सातवें वेतन आयोग के प्रति कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका कहना था कि सातवें वेतन आयोग से श्रमिक संगठनों ने केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन सिर्फ 18,000 रुपए की ही सिफारिश की गई है. उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की यह सिफारिश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विषय पर दिए गए आदेश के भी खिलाफ है. आयोग ने कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों को भी समाप्त करने की सिफारिश की है, जो निहायत नासमझी वाली बात है.

बाएं - डब्ल्यूआरएमएस के महामंत्री और एनएफआईआर के उपाध्यक्ष जे. जी. माहूरकर और दाएं - अध्यक्ष शरीफ खान पठान.

श्री माहूरकर के अलावा संघ के अन्य सदस्यों का यह भी कहना था कि उनकी नाराजगी वेतन आयोग के साथ ही रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों से भी है, जिन्होंने आयोग को रेल कर्मचारियों की मांगों और पूर्व में हुए वेतन संबंधी समझौतों से अनभिज्ञ रखा. श्री माहूरकर ने कहा कि यदि रेलकर्मियों की ये मांगें नहीं मणि गईं, और वेतन आयोग की सिफारिशों में समुचित सुधार नहीं किया गया, तो रेलकर्मियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह रेल हड़ताल मार्च के पहले हफ्ते में हो सकती है. उनके मुताबिक रेल कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल से देश को करीब चार हजार करोड़ का नुकसान होन निश्चित है, इसीलिए अब तक हड़ताल को टाला जा रहा था.

बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण

सुरेश त्रिपाठी

पेज 1 का शेष... में लगती है, लगभग उतनी ही जगह पर अवैध कब्जा हो चुका है. ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे की जमीन पर यह अवैध कब्जे जंगलों और पहाड़ों की पटरियों के किनारे नहीं, बल्कि नगरों और महानगरों में हुए हैं और लगातार होते जा रहे हैं. यहां इसके आर्थिक और सामाजिक विवेचन पर जाना जरूरी नहीं है.

भीषण ठंड अथवा चिलचिलाती गर्मी में ही नहीं, बल्कि किसी भी मौसम में लोगों को बेघर किया जाना अमानवीय है. इस पर चम्बल नदी में बचे-खुचे घड़ियाल भी आंसू नहीं बहाएंगे, मगर राजनीतिक लोग बहाते हैं. पहले वे खाली पड़ी रेलवे की या सरकारी जगहों पर लोगों को वोट बैंक की शक्ल में आबाद करते हैं, फिर उन्हें नगर परिषद अथवा महानगरपालिका का सम्पत्ति कर भरे जाने वाली रसीद मुहैया कराते हैं, बिजली के कनेक्शन नियमित करवाते हैं, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, यहां तक कि लाल-हरे और नीले-पीले राशन कार्ड भी बनवा डालते हैं! फिर इन मुफिलिसों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने और किसी भी मौसम में बरबाद होने के लिए लावारिस छोड़ देते हैं. मुंबई में साल-दर-साल ऐन घनघोर बारिश के बीच पटरियों के किनारे की झोपड़पट्टियों का उजाड़ दिया जाना समाचार बनता रहता है और बारहों महीने झुग्गियां रेल की पटरियों के किनारे खड़ी होती रहती हैं. भीषण सर्दी में दिल्ली की शकूरबस्ती को उजाड़े जाने का उदाहरण अभी ताजा ही है.

यदि रेलवे के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए, तो अकेले दिल्ली में रेलवे की 60 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है, जिसमें आबाद करीब 47000 झुग्गियों की वजह से रेलवे की 260 करोड़ की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधर में अटकी हुई हैं. दिल्ली में 60 हेक्टेयर जमीन का क्या मतलब होता है, इसका अंदाजा कोई अफसोस से भरा बिल्डर ही लगा सकता है. जहां तक शकूरबस्ती की बात है, तो रेलवे का कहना यह है कि अकेले इस बस्ती की वजह से 110 करोड़ रुपए का रेलवे टर्मिनल प्रभावित हुआ है. रेलवे का दूसरा दावा यह है कि अगर वे दयाबस्ती की अमर पार्क कॉलोनी और लॉरेंस रोड इलाके का अतिक्रमण हटा पाते, तो भटिंडा की रेल पटरी अम्बाला जाने वाली पटरी से जुड़ जाती. रेलवे की यह ग्रेड सेपरेटर परियोजना भी 156 करोड़ की है. मगर इसके लिए भी रेल प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है.

रेलवे की जमीन पर हर राज्य में अतिक्रमण है. हालांकि सरकारी आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तथापि रेल मंत्रालय के अनुसार उत्तर रेलवे की 210 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमित हो चुकी है. जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे की 159 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य जोनल रेलों और मंडलों में वास्तविक स्थिति क्या होगी. आज भी रेल प्रशासन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि वह अपनी ही जमीन से अवैध कब्जा करने वालों को पूरी तरह बेदखल कर सके. वैसे तो भारत में अपनी शुरुआत से लेकर आज तक के 163 वर्षों में रेलवे ने काफी तरक्की की है. आज उसकी पटरियों की लंबाई 65436 किमी. हो चुकी है. इन पटरियों पर 7172 रेलवे स्टेशन हैं. आज रेलवे के पास 2.40 लाख माल डिब्बे हैं, करीब 63 हजार सवारी डिब्बे हैं, 9 हजार से अधिक संख्या रेल इंजनों की है. इस पूरे उपक्रम को संचालित करने में 13.36 लाख कर्मचारी दिन-रात जुटे रहते हैं. वर्ष 2014-15 के दौरान 840 करोड़ लोगों ने भारतीय रेलों में सफर किया है. लेकिन शहरों के बीचोंबीच इसकी जमीन पर हुए अवैध कब्जे इसके सारे किए-कराए पर पानी फेर दे रहे हैं. ट्रेनें बचते-बचाते इस अंदाज में प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती हैं जैसे कोई नई-नवेली दुल्हन आ रही हो.

भारतीय रेल के पास अपार सम्पदा है, लेकिन जनता से करोड़ों रुपए का यात्री और माल भाड़ा वसूलने वाली रेलवे के पास आज पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, जो अतिक्रमण करने वालों पर कोई कार्रवाई कर सकें. स्थानीय असामाजिक तत्वों और राजनीतिज्ञों की मिलीभगत के कारण अपनी जान का जोखिम न लेकर रेलकर्मी भी रेलवे की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं. पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में रेल मंत्रालय अपनी मात्र 112 हेक्टेयर जमीन मुक्त करवा पाया है. दिल्ली में वर्ष 2003 और 2005 के बीच रेलवे ने दिल्ली सरकार को 4410 झुग्गियां हटाने के लिए 11.25 करोड़ रुपए दिए थे. लेकिन आज की तारीख तक यहां मात्र 297 झुग्गियां ही हटाई जा सकी हैं. दिल्ली में लगभग 70 किमी. की रेलवे लाइन दोनों तरफ से अतिक्रमण का शिकार है. लेकिन रेलवे इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है. अब इसका क्या किया जाए कि जब अवैध कब्जा हो रहा होता है, तब रेल प्रशासन सोता रहता है. उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन-आगर नैरो गेज लाइन बंद होने के 32 साल बाद भी रेल प्रशासन अपनी 159.901 हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश सरकार से वापस लेने में सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं पाया, क्योंकि वह उसे अपनी मिल्कियत ही साबित नहीं कर पाया था. देश भर में रेल अधिकारियों की अजगरी के ऐसे अनगिनत मामले हैं. प्रत्येक यात्री की सुविधा का ध्यान रखने वाली और अपनी आमदनी के एक रुपए में से 90 पैसे अपने कार्मिकों के वेतन-भत्तों और रख-रखाव पर खर्च करने वाली अंग्रेजों की मानसिकता वाले बाबुओं की शिकार हमारी भारतीय रेल अपनी हजारों करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन से अतिक्रमण हटाने के प्रति कतई गंभीर नहीं है. ऐसे में साफ-सुथरी छवि वाले रेलमंत्री सुरेश प्रभु को पता करना चाहिए कि रेलवे की मिल्कियत छुड़ाने के लिए कहां-कहां हाथ-पांव मारना होगा, क्योंकि रेल मंत्रालय के बाबू उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से गुमराह कर रहे हैं.

मात्र तीन-तीन डिवीजन वाली जोनल रेलों में एजीएम की अनावश्यक पोस्टिंग

- अधिकारियों के अनावश्यक बढ़ते पदों के कारण मुश्किल में पड़ता जा रहा है ट्रेन ऑपरेशन
- टटिया की आड़ से ट्रांसफर/पोस्टिंग में आईआरएसएस, आईआरएसईई अधिकारियों का फेवर

इलेक्ट्रिकल और स्टोर्स कैडर का फेवर करने के लिए अब तीन-तीन डिवीजन वाली बेहद छोटी जोनल रेलों में अपर महाप्रबंधक (एजीएम) की पोस्टिंग की गई है, जबकि सात नए जोन बनने के बाद से तीन डिवीजन वाली इन छोटी जोनल रेलों में एजीएम की पोस्ट को समाप्त करके उनका एलीमेंट अन्यत्र इस्तेमाल किया जा रहा था. परंतु अब निहितस्वार्थ या फेवर-वश इन छोटी रेलों में भी एजीएम की पोस्ट को पुनर्स्थापित किया गया है. इन छोटी जोनल रेलों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर, और पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर हैं. इनमें से उत्तर पश्चिम रेलवे (4 डिवीजन) को छोड़कर बाकी सभी में मात्र तीन-तीन डिवीजन ही हैं.

जैसा कि 'रेलवे समाचार' ने पहले ही लिखा था कि सीआरबी, मेंबर इलेक्ट्रिकल और सेक्रेटरी/रे.बो. के बीच जोनल रेलों में डीआरएम/एडीआरएम, एजीएम, एसडीजीएम आदि कई महत्वपूर्ण पदों पर स्टोर्स, इलेक्ट्रिकल और एसएंडटी के अधिकारियों की पोस्टिंग को वरीयता दिए जाने का गुपचुप 'पैक्ट' हुआ है. अब वह सही साबित हो रहा है. इसके अलावा उक्त खबर के बाद रेलवे बोर्ड (सीआरबी) ने एक बयान देकर उक्त 'पैक्ट' को उचित ठहराते हुए मीडिया को बताया था कि 'इन कैडर्स के अधिकारी रेलवे वर्किंग में काफी पिछड़ गए हैं, इसलिए उन्हें आगे लाने के लिए उनकी नियुक्ति ऐसे पदों पर की जा रही है.' "क्या बेशर्मी है, यह बयान देते हुए अब तक भी स्टोर्स क्लर्क की सोच से ऊपर नहीं उठ पाए सीआरबी को तनिक भी अपने पद और गरिमा का ख्याल नहीं रहा." यह कहना है विभिन्न कैडर के अधिकारियों का.

बहरहाल, टटिया की आड़ से कैडर को फेवर करने का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एचएजी में जूनियर मोस्ट अनिल कुमार गुप्ता (एसएजी/आईआरएसईई/पू.रे.) को एचएजी में प्रमोट करके द.म.रे. में एजीएम बनाया गया है. हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है इसमें कुछ भी गलत नहीं है. तथापि परंपरा और नैतिकता के हिसाब यह गलत है. जबकि परंपरा और नैतिकता का तकाजा अब तक यह रहा है कि सम्बंधित कैडर में सबसे सीनियर मोस्ट को ही एजीएम बनाया जाता रहा है, जिससे उसे जोन के सभी एचओडी/पीएचओडी, डीआरएम आदि सहित अन्य अधिकारियों द्वारा जीएम के बराबर सम्मान की दृष्टि से देखा जाए. उल्लेखनीय है कि एजीएम ही जोन के सभी डीआरएम की कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, वही डीआरएम की एसीआर भी लिखता है. तमाम हाई कास्ट टेंडर्स, रीकास्ट टेंडर्स, कास्ट वेरिएशन आदि की एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी एजीएम ही होता है. सवाल जूनियर मोस्ट के सक्षम और योग्य होने का नहीं है, बल्कि सवाल परंपरा और नैतिकता का है.

इसी प्रकार वीरेंद्र कुमार (आईआरएसएमई) को द.पू.म.रे. में सीएमई/एसएजी से एचएजी में प्रमोट करते हुए सीधे एजीएम बनाया गया है. इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर की सीएमई की पोस्ट का एचएजी एलीमेंट अस्थाई तौर पर द.पू.म.रे में एजीएम की पोस्ट को ऑपरेट करने के लिए ट्रांसफर किया गया है. जबकि टी. पी. सिंह, एसडीजीएम/म.रे., (एसएजी) को एचएजी में पदोन्नत करके पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर में एजीएम बनाया गया है और वहां एजीएम की पोस्ट को री-स्टोर किया गया है, जिसका एलीमेंट पूर्व एजीएम अजय शुक्ला का रेलवे बोर्ड में ट्रांसफर होने के बाद से उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर में एजीएम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण एस. एल. वर्मा (एचएजी/आईआरएसई) को पूर्वोत्तर रेलवे में ही एजीएम बना दिया गया है, जिसके लिए सीई/सी/प्लानिंग/उ.रे. (पोस्ट कोड-12543) और पीसीई/पू.म.रे. (पोस्ट कोड-675) के एचएजी एलीमेंट का उपयोग किया गया है. जबकि पांच डिवीजनों वाली पूर्व मध्य रेलवे में प्रॉपर एचएजी/पीसीई का होना ज्यादा जरुरी था. इसी प्रकार एजीएम/पू.रे. की 31 दिसंबर को खाली हुई पोस्ट पर उत्तर मध्य रेलवे के पीसीई सतीश कुमार (एचएजी/आईआरएसई) को एजीएम पदस्थ किया गया है. उपरोक्त सभी एजीएम की पोस्टिंग्स में सिर्फ सतीश कुमार की ही एकमात्र प्रॉपर पोस्टिंग कही जा सकती है. बाकी सभी पोस्टिंग जोड़-तोड़ के तहत की गई प्रतीत हो रही हैं. इनमें से तीन-तीन डिवीजनों वाली रेलों में की गई एजीएम की पोस्टिंग्स सिर्फ रेलवे रेवेन्यु की वेस्टेज ही कही जा रही हैं, जिसकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं थी.

पोस्टिंग में आईआरएसएस, आईआरएसईई अधिकारियों का फेवर

इसके अलावा फेवर करने की हद ये है कि महीनों पहले की गई पोस्टिंग्स को रद्द करके सम्बंधित अधिकारियों के मन-मुताबिक पोस्टिंग भी दी जा रही है. इस बात का उल्लेख पहले भी 'रेलवे समाचार' ने किया था. उल्लेखनीय है कि चेयरमैन, आरआरबी/मुजफ्फरपुर रहे वी. पी. एन. तिवारी (एसएजी/आईआरएसईई) का ट्रांसफर 22 जुलाई 2015 को सीएलडब्ल्यू/चितरंजन में कैडर में किया गया था. इसे 29 दिसंबर को रद्द करके अब पूर्वोत्तर रेलवे में कर दिया गया है. जबकि पूर्व रेलवे के मनोरंजन बिस्वास (एसएजी/आईआरएसईई) का ट्रांसफर 2 नवंबर 2015 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में किया गया था. इसे भी 29 दिसंबर को रद्द करके अब उन्हें सीएलडब्ल्यू/चितरंजन में कर दिया गया है. राजीव खंडेलवाल (एसएजी/आईआरएसएस) को उनके निवेदन पर दक्षिण रेलवे से दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता में पी. सी. मिश्रा की जगह पदस्थ किया गया है, और श्री मिश्रा को पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर भेज दिया गया है. इसी तरह अकेले अजीत कुमार सिन्हा (एसजी/ आईआरएसएस) को डीएलडब्ल्यू से द.पू.रे. में उनके मन-मुताबिक फेवर करने के लिए चार अन्य अधिकारियों - मनोज कुमार, आकाश दीप, अजीत सिंह यादव एवं आर. पी. तिवारी - को दरबदर किया गया.

जबकि ए. मुथुस्वामी (जेएजी/आईआरएसएस) को उनके निवेदन पर 21 मई 2015 को पू.त.रे. से द. रे. में ट्रांसफर कर दिया गया था. उक्त आदेश को करीब आठ महीने बाद 22 दिसंबर को रद्द करके अब श्री मुथुस्वामी को द.प.रे., हुबली जाने का आदेश जारी किया गया है. इसी प्रकार आर. आर. पाटिल (जेएजी/आईआरएसएस) को म. रे. से द.पू.म.रे. में तबादले का आदेश 5 मई 2015 को जारी किया गया था, जिसे अब आठ महीने बाद 22 दिसंबर को रद्द कर दिया गया है. सर्वेश चंद द्विवेदी (जेएस/आईआरएसएस) को उनके मन-मुताबिक पू.म.रे. से उ.म.रे. में भेज दिया गया. इसी तरह डॉ. आर. त्रिवेदी (एसएजी/आईआरएमएस) का तबादला 1 दिसंबर को डीएलडब्ल्यू से प. रे., मुंबई में सीएमएस/एमडी के पद पर किया गया था. अब इसे 28 दिसंबर को रद्द करके उन्हें डीएलडब्ल्यू में ही बतौर सीएमएस/एमडी/सीएमओ पदस्थ कर दिया गया है. जबकि 10 नवंबर को द.म.रे. से पी. नेहेमिया (एसएस/आईआरपीएस) का तबादला पू.त.रे. में किया गया था, उसे 21 दिसंबर को रद्द कर दिया गया. जबकि दो साल के समय में श्री नागाईच (सीनियर एसएजी/आईआरपीएस) का तबादला चार बार किया जा चुका है, जबकि उनके रिटायरमेंट में लगभग डेढ़ साल का समय बाकी है.

इलेक्ट्रिकल कैडर के अधिकारियों की एचएजी में पदोन्नति एवं नियुक्ति

सीईई/कोर, इलाहाबाद लोकेश नारायण की एचएजी में पदोन्नति करके उन्हें सीईई/उ.म.रे. के पद पर नियुक्त किया गया है. जबकि सीईई/डीएलडब्ल्यू योगेश अस्थाना (एचएजी) को डीएलडब्ल्यू से ट्रांसफर करके उन्हें लोकेश नारायण की जगह कोर, इलाहाबाद में नियुक्त किया गया है. गौरव दवे को एचएजी में पदोन्नत करके उत्तर रेलवे से श्री अस्थाना की जगह शेष पेज 5 पर...

रेलवे और राज्यों की संयुक्त उपक्रम बनाने का रास्ता साफ

देश में नौकरशाही के और ज्यादा विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ीं

दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 30 दिसंबर को रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों की वित्तीय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों के साथ रेलवे की संयुक्त उपक्रम कंपनियां बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इससे केंद्र को रेलवे की विभिन्न बुनियादी एवं ढांचागत परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि राज्यों के साथ बनने वाले ऐसे संयुक्त उपक्रमों में रेल मंत्रालय और राज्यों की शुरुआती चुकता पूंजी 50-50 करोड़ रुपए तक सीमित रहेगी. संयुक्त उपक्रम से राज्यों की वित्तीय सहभागिता के अलावा निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी तेज होगी तथा संबंधित राज्यों में रेल परियोजनाओं पर अमल में तेजी सुनिश्चित हो.

इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार रेलवे और संबंधित राज्य सरकार की इक्विटी भागीदारी से संयुक्त उपक्रम कंपनियां बनाई जाएंगी. इससे रेल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. वित्तीय तंगी के चलते कई रेल परियोजनाओं में देरी होती है. संयुक्त उपक्रम कंपनी की शुरुआती चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी, जो कि परियोजनाओं के आकार पर निर्भर होगी. सक्षम प्राधिकरण से परियोजना की मंजूरी और उसके वित्तपोषण की मंजूरी के बाद परियोजनाओं के लिए और कोष-इक्विटी जुटाई जाएगी.

इसके अलावा किसी संयुक्त उपक्रम परियोजना विशेष के लिए विशेष उद्देश्यीय इकाई भी बनाई जा सकती हैं, जिनमें बैंक, बंदरगाह, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, खनन कंपनियां आदि की भी हिस्सेदारी हो सकती है. इससे रेल परियोजनाओं में राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ेगी. वह परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद देने के साथ-साथ निर्णय प्रक्रिया में भी भाग ले सकेंगे. राज्यों की इनमें भागीदारी होने से परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण सहित दूसरी सांविधिक मंजूरियां भी जल्दी प्राप्त हो सकेंगी. तथापि, जानकारों का कहना है कि इस प्रकार के विस्तार से सरकार की मंशा पूरी हो या न हो, मगर यह बात तय है कि इससे अधिकारियों की एक नई फ़ौज खड़ी होगी और वर्तमान अधिकारियों को इन नए घोसलों का फायदा मिलेगा.

सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को महाप्रबंधक के हाथों समापक भुगतान

इलाहाबाद ब्यूरो : उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय सभागृह में 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के समापक भुगतान समारोह का आयोजन किया गया. समारोह की अध्यक्षता महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे अरुण सक्सेना ने की. श्री सक्सेना ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में रेल सेवा से निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि रेलवे की प्रगति में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए उन्हें मानार्थ पास, मेडिकल कार्ड, मेडल एवं समापक भुगतान के प्रपत्र सौंपे.

उत्तर मध्य रेलवे के सेवानिवृत्त मुख्य विद्युत इंजीनियर भरत कुमार सोनावने को समापक भुगतान के प्रपत्र सौंपते हुए महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे अरुण सक्सेना. उनके साथ हैं मुख्य कार्मिक अधिकारी ओमप्रकाश.

इस अवसर पर सेवानिवृत्त उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य विद्युत इंजीनियर भरत कुमार सोनावने, मुख्य विद्युत वितरण इंजीनियर इरफान बेग, मुख्य स्वास्थ्य निदेशक उत्कर्ष बंसल और सहायक सुरक्षा अयुक्त बाबूलाल सहित कुल 8 अधिकारी एवं कर्मचारियों को महाप्रबंधक अरुण सक्सेना ने अपने हाथों से समापक भुगतान सौंपा. इस अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी ओमप्रकाश सहित मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे.

ऑल इंडिया इंटर रेलवे फुटबाल टूर्नामेंट में चैंपियन का ख़िताब जीतने के बाद मेट्रो रेलवे, कोलकाता की फुटबाल टीम एवं अन्य खिलाड़ियों के साथ महाप्रबंधक ए. के. कपूर.

ऑल इंडिया इंटर रेलवे फुटबाल टूर्नामेंट में मेट्रो रेलवे की टीम बनी चैम्पियन

कोलकाता : 72वें ऑल इंडिया इंटर रेलवे फुटबाल टूर्नामेंट में मेट्रो रेलवे, कोलकाता की फुटबाल टीम ने पश्चिम रेलवे को 2-0 गोल से हराकर चैंपियन का ख़िताब हासिल किया. यह फाइनल टूर्नामेंट 18 दिसंबर को रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ), कपुरथला खेला गया. मेट्रो रेलवे की टीम के असीम बिस्वास और अनिल किस्कू ने एक-एक गोल किया. मेट्रो रेलवे की फुटबाल टीम ने अपने ग्रुप की सभी टीमों को हराते हुए क्वालीफाइंग राउंड में टॉप पोजीशन हासिल की थी. मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक ए. के. कपूर ने अपने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके खेल और जज्बे की सराहना की है. इसके अलावा ब्रिज एवं चेस में भी मेट्रो रेलवे की टीमों की परफोर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है. मेट्रो रेलवे की ब्रिज टीम में सुमित बनर्जी, देवब्रत मजूमदार, अनिंद्र कुमार सरकार, अनूप दत्ता, गौतम बनर्जी और तपन भट्टाचार्जी शामिल थे. यह 38वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे ब्रिज चैंपियनशिप 13 से 15 अक्टूबर को पी. एल. रॉय स्टेडियम, सियालदह, कोलकाता में खेली गई थी. 2 दिसंबर को नेताजी इंडोर स्टेडियम, कोलकाता में आयोजित एक सम्मान समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेस ग्रैंड मास्टर सप्तर्षि रॉय चौधरी को 'खेल सम्मान अवार्ड 2015-16' से सम्मानित किया.

मात्र तीन-तीन डिवीजन वाली जोनल रेलों में एजीएम की...

पेज 4 का शेष... डीएलडब्ल्यू भेजा गया है. सीईई एम. के. माथुर को पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से समान पद पर दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली भेजा गया है. इसी प्रकार श्री माथुर की जगह बी. वी. चंद्रशेखर को एचएजी में पदोन्नत करके द.रे. से पू.म.रे. में भेजा गया है. पंकज गुप्ता को एचएजी में पदोन्नत करके सीएलडब्ल्यू में ही सीईई की पोस्ट को अपग्रेड करके वहीं पदस्थ किया गया है. इसी प्रकार हरिंद्र राव को एचएजी में पदोन्नति देकर बतौर सीईई (पीएचओडी) दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता में ही पदस्थ कर दिया गया है. इसी तरह एस. एन. सिंह और राजीव अग्रवाल को भी एचएजी में पदोन्नत करके उन्हें क्रमशः पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर और मध्य रेलवे, मुंबई में ही उनके पदों पर बतौर सीईई (पीएचओडी) नियुक्त कर दिया गया है, जहां वे अब तक सीएचओडी के रूप में कार्यरत थे. जबकि एल. सी. सारसर (एसएजी) को पश्चिम रेलवे से ट्रांसफर करके पूर्व रेलवे में सीईई (सीएचओडी) के पद पर पदस्थ किया गया है.

इंजीनियरिंग अधिकारियों की पदोन्नति एवं तबादले

पीसीई/पू.म.रे. जगदीप राय (एचएजी/आईआरएसई) को पटना से ट्रांसफर करके उत्तर रेलवे निर्माण संगठन, दिल्ली में सीएओ/2 बनाया गया है. जबकि आर. के. मीना (पीसीई/एसएजी) को एचएजी में पदोन्नत करके दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता में ही पीसीई/पीएचओडी बना दिया गया है. सीएओ/सी/एन, पूर्व मध्य रेलवे बी. पी. गुप्ता को एचएजी में वहीं पदोन्नत कर दिया गया है. संजीव रॉय (पीसीई/एसएजी) को एचएजी में पदोन्नत करके दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली में ही पीसीई/पीएचओडी बनाया गया है. इसी प्रकार ललित कपूर (पीसीई/एसएजी) और एस. एस. गुप्ता को एचएजी में पदोन्नत करके क्रमशः पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, गुवाहाटी और दक्षिण रेलवे में ही पीसीई/पीएचओडी पदस्थ कर दिया गया है. जबकि पी. के. मिश्रा (एसएजी/आईआरएसई) को पश्चिम रेलवे, मुंबई से ट्रांसफर करके पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर में जगदीप राय की जगह एचएजी पोस्ट को डाउनग्रेड करके पीसीई/एसएजी में पदस्थ किया गया है.

मैकेनिकल अधिकारियों की उसी जगह एचएजी में पदोन्नति

पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर में सीएमई/सीएचओडी के पद पर कार्यरत राजेश अग्रवाल को एचएजी में पदोन्नत करके वहीं सीएमई/पीएचओडी बनाया गया है. जबकि आईसीएफ में सीएमई/सीएचओडी रहे एल. सी. त्रिवेदी को एसएजी में उसी जगह पदोन्नत कर दिया गया है. इसी प्रकार आईसीएफ/रायबरेली में सीएओ/सीएचओडी रहे हर्ष कुमार को भी उसी जगह एचएजी में पदोन्नत करके सीएओ/पीएचओडी बना दिया गया है. वी. के. एम. जी. बाबतीवाले को भी एचएजी में प्रमोट करके सीएमई बनाया गया है. हालांकि उनके नाम के आगे रेल कोच फैक्ट्री लिखा गया है, परंतु यह 'रेल कोच फैक्ट्री' कौन सी है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है. जबकि पोस्टिंग में 'रेलवे' लिखा गया है, मगर पोस्टिंग ऑर्डर में यह कौन सी 'रेलवे' है, यह भी स्पष्ट नहीं है. अनिर्बान दत्ता को भी सीएमई/पीएचओडी के रूप में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, गुवाहाटी के पद पर वहीं कन्फर्म कर दिया गया है. इसी तरह पूर्व तट रेलवे में सीएमई/सीएचओडी के पद पर कार्यरत अनिल कुमार शर्मा को भी एचएजी में पदोन्नत करके वहीं सीएमई/पीएचओडी बना दिया गया है.

चार ट्रैफिक अधिकारियों की पोस्टिंग, तीन माह से सीसीएम/द.रे. का पद खाली

21 दिसंबर को चार ट्रैफिक अधिकारियों की प्रॉपर एसएजी में पोस्टिंग होने से ट्रैफिक विभाग को थोड़ी गति मिलती नजर आई है. दक्षिण रेलवे में कार्यरत के. मनोज (एसजी/आईआरटीएस) को एसएजी में पदोन्नत करके द. रे. कैडर में ही पदस्थ कर दिया गया है. तथापि द. रे. में करीब तीन महीने से खाली पड़ी सीसीएम की पोस्ट पर नियुक्ति का अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. ऐसा लगता है कि इस पद पर स्थानीय प्रशासन और रेलवे बोर्ड के बीच कोई खींचतान चल रही है. यदि ऐसा कुछ है, तो इसका खुलासा भी जल्दी ही हो जाएगा. उधर राधेश्याम को एसएजी में प्रमोट करके पूर्वोत्तर रेलवे में ही पोस्टिंग दे दी गई है. जबकि पश्चिम रेलवे में कार्यरत श्रीमती अंजू मोहनपुरिया (सुरेंद्र) को एसएजी में पदोन्नत करके पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर भेजा गया है. इसके अलावा पूर्व तट रेलवे में कार्यरत वरिंदर कुमार को एसएजी में प्रमोट करके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में पदस्थ किया गया है. अब जरूरत इस बात की है कि ट्रैफिक कैडर के जो तमाम अक्षम अधिकारी विभिन्न जोनल मुख्यालयों और मंडलों में परिणामदाई पदों पर काफी लम्बे अर्से से पदस्थ हैं, उन्हें दरकिनार करके उक्त पदों पर लाया जाए. क्योंकि इन अधिकारियों की अक्षमता या अयोग्यता अथवा ऐसे पदों पर काम करने का कम अनुभव होने के कारण विभिन्न जोनों/मंडलों की लोडिंग कम हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे की वास्तविक अर्निंग काफी तेजी से गिरी है. रेलवे बोर्ड और जोनल मुख्यालयों में बैठ कुछ चालाक बाबू लोग भले ही रेलमंत्री को गुमराह कर लें, मगर जमीनी हकीकत यही है कि कई प्रमुख रेलों की लोडिंग घटी है, जिससे चालू वित्तवर्ष के पहले नौ महीनों में उनकी वास्तविक अर्निंग निर्धारित लक्ष्य से काफी कम हुई है. अब साल के बाकी बचे तीन महीनों में या तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, जो कि काफी मुश्किल नजर आ रहा है, या फिर हमेशा की तरह पैटर्न बदलकर आंकड़ों का खेल खेला जाएगा. जो कि 'सीए' रेलमंत्री होने से अधिकारियों के लिए काफी आसान भी हो गया ह

भारतीय रेल आम आदमी के परिवहन का माध्यम है –मनोज सिन्हा

- बटेश्वर से गाड़ी चलने से 16 साल बाद अटलबिहारी बाजपेई का सपना पूरा हुआ

आगरा : उत्तर मध्य रेलवे, आगरा मंडल के बटेश्वर हाल्ट स्टेशन पर रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा एवं मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने महाप्रबंधक/उ.म.रे. अरुण सक्सेना की उपस्थिति में 24 दिसंबर को स्पेशल डीएमयू ट्रेन संख्या 07191 बटेश्वर–इटावा को हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ किया. इस अवसर पर रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने अपने सम्बोधन में कहा कि यह गाड़ी स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं नागरिकों के प्रयासों के फलस्वरूप चलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार सवा दो गुना हुआ है, जबकि यात्रियों की संख्या में 16 गुना और माल यातायात में 8 गुना का इजाफा हुआ है. उन्होंने एक बार फिर से इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय रेल अब तक 'अंडर इंवेस्टमेंट' का शिकार रही है, जिसके कारण भारतीय रेल के विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में 1.10 लाख करोड़ तथा अगले 5 वर्षों में 8 लाख करोड़ यूपे का निवेश किया जाएगा. इससे रेलवे के विकास

को नई गति मिलेगी.

रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय रेल आम आदमी के परिवहन का माध्यम है, इसको और अधिक सुविधायुक्त एवं आरामदायक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और रेलमंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व मे रेल प्रशासन निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम भी, जिसमें आगरा-इटावा (वाया बटेश्वर) नवनिर्मित रेल लाइन पर डेमू यात्री सवारी गाडी का शुभारंभ किया जा रहा है, रेल मंत्रालय के इन्हीं प्रयासों में से एक है. यह ट्रेन आगरा एवं इटावा के मध्य दैनिक यात्रियों को एक बडी सुविधा प्रदान करेगी. रेल राज्यमंत्री ने निकट भविष्य में आगरा–इटावा रेलखंड पर चार गाड़ियां - इलाहाबाद-जयपुर एक्सप्रेस, कोटा-पटना एक्सप्रेस, जोधपुर–हावड़ा एक्सप्रेस एवं उद्यान–आभा तूफान एक्सप्रेस को शुरू करने की भी जानकारी दी. उन्होंने बटेश्वर स्टेशन के विकास एवं विस्तारीकरण की भी बात कही.

रेल राज्यमंत्री ने कहा कि इस रेल लाइन की योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल में वर्ष 1999-2000 के दौरान बनाई गई थी. श्री बाजपेयी ने ही वर्ष 1999 में इसकी आधारशिला रखी थी. इस योजना के पूरा होने और उनके पैत्रिक गांव बटेश्वर में उनके जन्मदिन के अवसर पर इसका उदघाटन होने से उनका सपना पूरा हुआ है. श्री सिन्हा ने कहा कि इस बजट में पलवल–मथुरा चौथी लाइन कुल लागत 524 करोड़ रुपए, मथुरा-झांसी तीसरी लाइन की कुल लागत 2488 करोड़ रुपए तथा झांसी-बीना तीसरी लाइन की कुल लागत 1162 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं. सभी ए-1, ए एवं बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई/ब्रॉड बैंड सुविधा आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है. गूगल के साथ एक समझौता करके रेलटेल सभी ए-1 एवं ए श्रेणी के स्टेशनों (कुल 400) पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने आगरा मंडल को सकल आय में पिछले वर्ष की तुलना में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के लिये बधाई भी दी. आगरा कैंट स्टेशन पर कार्यरत स्वचालित सीढ़ियां एवं मथुरा स्टेशन पर निर्माणाधीन स्वचालित सीढ़ियां यात्री सुविधाओं में योगदान हैं. यहां शीघ्र ही एक्सीक्यूटिव लाउंज की सुविधा भी यात्रियों को प्रदान की जाएगी.

इस अवसर पर मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने कहा कि इस क्षेत्र में रेलगाड़ियां चलने से विकास का एक नया रास्ता खुलेगा. सांसद बाबू लाल ने इस क्षेत्र में रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर केंद्रीय विद्यालय भी खोलने की मांग की. उन्होंने फतेहपुर सीकरी स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग तथा आगरा कैंट पर राजधानी सहित सभी ट्रेनों के ठहराव की भी मांग की. भिंड लोकसभा क्षेत्र के सांसद भागीरथ प्रसाद ने नई रेल लाइन खुलने पर हर्ष व्यक्त किया.

इस मौके पर महाप्रबंधक/उ.म.रे. अरुण सक्सेना ने रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया सहित सभी उपस्थितों और जनसमूह का स्वागत किया. इस अवसर पर पूर्व सांसद एस. पी. सिंह बघेल, पूर्व सांसद प्रभू दयाल कठेरिया, विधायक जगन प्रसाद गर्ग, विधायक योगेंद्र उपाध्याय, पूर्व महापौर श्रीमती बेबी रानी मौर्या सहित अपर महाप्रबंधक वाई. पी. सिंह, मुख्य परिचालन प्रबंधक अनुराग, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक डॉ. डी. के. त्रिपाठी, मंडल रेल प्रबंधक प्रभाष कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बिजय कुमार आदि अधिकारीगण उपस्थित थे. अंत में मंडल रेल प्रबंधक प्रभाष कुमार ने सभी को धन्यवाद दिया. कार्यक्रम के सफल आयोजन पर रेल राज्यमंत्री ने रेलकर्मियों को तीन लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की.

चार–पांच महीनों से अनमैंड चल रही है वलसाड–दाहोद–वलसाड इंटरसिटी

- पश्चिम रेलवे को हो रहा है रोजाना करीब एक लाख रुपए का नुकसान
- सभी जोनल रेलों की वाणिज्यिक आय सहित माल भाड़ा आय भी तेजी से गिरी

दाहोद : पश्चिम रेलवे की गाड़ी संख्या 19059/19060 वलसाड-दाहोद-वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस पिछले करीब चार-पांच महीनों से बिना किसी टिकट चेकिंग स्टाफ के ही चल रही है. लंबे समय से इस गाड़ी में किसी भी टिकट चेकिंग स्टाफ की तैनाती नहीं की जा रही है. इससे इस गाड़ी में कम दूरी के तमाम यात्री बिना टिकट तो चलते ही हैं, बल्कि ये यात्री इसके एकमात्र एसी चेयरकार कोच में भी बड़े आराम से निर्द्वंद होकर यात्रा करते हैं, क्योंकि उन्हें चेक करने वाला को नहीं होता है. इससे प्रतिदिन रेलवे को करीब एक लाख रुपए की आय का नुकसान हो रहा है. तथापि यह मामला रेल प्रशासन के संज्ञान में लाए जाने के एक हफ्ते बाद भी इस गाड़ी में टिकट चेकिंग स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल की इस गाड़ी के वलसाड और दाहोद के बीच प्रतिदिन दो फेरे होते हैं. इसके प्रथम श्रेणी कोच को निकालकर एसी चेयरकार का एक कोच लगाया था, जिसमें 70 सीटें हैं. यदि औसतन वलसाड से दाहोद का इसका एकतरफा किराया एक यात्री का 500 रुपए माना जाए, तो इस एक कोच से रोजाना पश्चिम रेलवे को लगभग 70 हजार रुपए की आय का नुकसान हो रहा है. जबकि इसमें जो बाकी सामान्य यात्री बिना टिकट चल रहे हैं, उनकी तो कोई गणना ही नहीं है. हालांकि बताते हैं कि यदाकदा टिकट चेकिंग स्टाफ के उड़नदस्ते इस गाड़ी की जांच करते हैं, मगर उससे इसमें चलने वाले बेटिकट यात्रियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है. इस संदर्भ में करीब एक हफ्ते पहले 'रेलवे समाचार' द्वारा रेलमंत्री सहित पश्चिम रेलवे प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, मगर अब तक इस गाड़ी में मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा टिकट चेकिंग स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है. जबकि टिकट चेकिंग से होने वाली आय को बढ़ाने पर प्रशासन द्वारा लगातार चेकिंग स्टाफ पर भारी दबाव बनाया जाता है और उन्हें 'टारगेट' भी दिया जाता है. कई वरिष्ठ रेल अधिकारियों का कहना है कि जब रेलमंत्री ने जीएम, डीआरएम सहित जोनल एवं मंडल मुख्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर गाड़ियां चलाने तथा समुचित यात्री-सुविधाएं मुहैया कराने के उनके मुख्य काम के बजाय यात्रियों को खाना पहुंचाने, उनकी शिकायतों का तत्काल समाधान करने, दवा देने, दूध पिलाने, चलती गाड़ियों में झाड़ू-पोंछा लगाने, स्टेशनों की सफाई करने जैसे ट्रेन ऑपरेशन से इतर कार्यों में लगा रखा है, तब रेलवे की आय की किसको चिंता है. उनका यह भी कहना है कि यही वजह है कि लगभग सभी जोनल रेलों की वाणिज्यिक आय सहित माल भाड़ा आय भी तेजी से गिरी है.

राज्य सरकारें अब तय करेंगी रेलवे की नीतियां

उदयपुर : रेलवे का विकास अब राज्य सरकारों की सलाह से किया जाएगा, रेलवे की नीतियों के निर्धारण में अब राज्य सरकारों की सलाह को प्रमुखता दी जाएगी. यह कहना है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए. के. मितल का. श्री मितल आजकल कथित निरीक्षण के बहाने वर्ष के अंतिम दिनों की छुट्टियां मनाने उदयपुर और जोधपुर आए हुए हैं. उनके साथ उत्तर पश्चिम रेलवे का भी पूरा लवाजमा मौजूद है. इस निरीक्षण उर्फ घुमक्कड़ी कार्यक्रम के दौरान सीआरबी श्री मितल ने नाथद्वारा में भी प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर में दर्शन किए. यहां उन्होंने स्थानीय जनता को नाथद्वारा रेलवे स्टेशन को मुख्य शहर के पास लाकर स्थापित किए जाने का आश्वासन भी दिया. बजट और लागत के बारे में

उनका कहना था कि इसकी कोई समस्या नहीं है. इसकी अनुमानित लागत का प्रस्ताव मिलते ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

स्थानीय पत्रकारों से एक बातचीत में सीआरबी ने कहा कि एक संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर कंपनी) के माध्यम से राज्यों में रेलवे का विकास किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव को राजस्थान सहित 17 राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है. उनका कहना था कि रेलवे के विकास में अब राज्य भी अपने सुझाव दे सकेंगे.

उल्लेखनीय है कि अब तक रेलवे की नीतियां सिर्फ केंद्र सरकार ही तय करती रही है. परंतु सीआरबी श्री मितल के अनुसार अब रेलवे की नीतियों में राज्य सरकारों की सलाह को प्रमुखता दी जाएगी. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ए. के. मितल ने यह जानकारी यहां शनिवार, 26 दिसंबर को उदयपुर स्टेशन के निरीक्षण करते हुए स्थानीय मीडिया को दी है. श्री मितल ने यहां स्टेशन पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया. उनके साथ उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अनिल सिंघल, डीआरएम नरेश सालेचा ने उदयपुर स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की जानकारी सीआरबी को दी.

स्थानीय सांसद अर्जुन लाल मीणा ने सीआरबी को मिलकर उन्हें स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया. उनसे बातचीत के बाद श्री मितल ने बताया कि महत्वाकांक्षी उदयपुर-अहमदाबाद ब्रॉडगेज लाइन पर कुल 800 से 900 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि फंड की कमी के चलते पिछले वर्ष इस लाइन के निर्माण में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई. परंतु हाल ही में 150 करोड़ का फंड इसके लिए उपलब्ध कराया गया है. यहां सबसे पहले कुल 43 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस महत्वपूर्ण ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण कार्य अगले तीन साल में पूरा कर लिया जाएगा.

सीआरबी का यह बयान अत्यंत विवादास्पद है, क्योंकि राज्यों द्वारा अपने राज्य के दायरे में रेल यातायात की सुविधा बढ़ाने हेतु पहले से ही सीधे अथवा सांसदों के माध्यम से रेलवे को अपनी जरूरतें भेजी जारी हैं. इन पर रेलवे द्वारा सर्वे भी कराया जाता है. इसी के चलते पिछले 68 सालों में सैकड़ों रेल परियोजनाएं कागजी साबित हुई हैं और ऐसी सैकड़ों रेल परियोजनाएं आज भी लंबित हैं. जबकि ऐसी ही सैकड़ों रेल लाइनें रेलवे के लिए भारी घाटे का सौदा साबित हुई हैं, जो सिर्फ स्थानीय सांसदों की राजनीति चमकाने के लिए बना दी गई थीं. अब यदि रेलवे की नीतियां तय करने में राज्यों की सलाह को प्रमुखता दी गई, तो क्या होगा? इसका अंदाज भी आसानी से लगाया जा सकता है. आजादी के बाद लगातार देश पर शासन करके जो गलतियां कांग्रेस नीत केंद्र सरकारों ने की और केंद्र को कमजोर बनाया, अब उन्हीं गलतियों को भाजपा नीत केंद्र सरकार भी दोहराने जा रही है. मोदी सरकार को चाहिए कि वह सबसे पहले इस रीढ़हीन नौकरशाही को दुरुस्त करे, वरना केंद्र की सत्ता में राजनीतिक पार्टियां बदल-बदलकर यह सिद्धांतविहीन नौकरशाही देश को बरबाद कर देगी.

सातवें वेतन आयोग से...

पेज 1 का शेष... किराया और माल भाड़ा बढ़ा देना ही रेलवे के पास अपनी आय बढ़ाने का एक ही रास्ता है. हालांकि इस संबंध में रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने वित्तमंत्री अरुण जेटली से भी बात की है, मगर उनके बीच हुई इस बातचीत का कोई खुलासा नहीं हो पाया है. तथापि सूत्रों का कहना है कि रेलमंत्री ने आगामी आम बजट में रेलवे का बजटरी सहयोग बढ़ाए जाने की मांग की है. जबकि हाल ही में टिकट रद्दीकरण शुल्क और तत्काल चार्जेज बढ़ाए जाने को भी इसी की पूर्व तैयारी के रूप में देखा जाना चाहिए. तथापि इसके बाद भी यदि बजट में रेल किराया और बढ़ाए जाने की संभावना पैदा होती दिखती है, तो इससे जनता के बीच केंद्र की भाजपा नीत सरकार के विरुद्ध और माहौल बनेगा.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले रेलमंत्री वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखकर कहा है कि वेतन आयोग का बोझ वहन करने के लिए केंद्र सरकार उनकी मदद करे, क्योंकि रेलवे को माल भाड़े से होने वाली आय भी लक्ष्य से काफी कम है. इसके अलावा रेलमंत्री ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को एक अन्य पत्र लिखकर कहा है कि वे रेलकर्मियों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) से मुक्त कर दें, क्योंकि रेल संगठनों की यह बहुत पुरानी मांग है और इसके न माने जाने पर रेल संगठन संघर्ष करने पर उतारू हैं, जिससे देश में औद्योगिक अशांति फैलने का खतरा बना हुआ है. हालांकि वित्त मंत्रालय द्वारा श्री प्रभु की बात माने जाने की उम्मीद कम ही है. तथापि रेलकर्मियों या मजदूरों को बरगलाए रखने के लिए श्रमिक संगठनों और सरकार के बीच चिट्ठी रूपी नूरा-कुस्ती का चलते रहना जरूरी है.

गोमतीनगर टर्मिनस : क्या मोदी सरकार पूरा करेगी बाजपेई का ड्रीम प्रोजेक्ट?

वाराणसी की तरफ लगा है अब चापलूस और मौकापरस्त नौकरशाही का पूरा ध्यान

लखनऊ : पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेई के जन्मदिन 25 दिसंबर को भाजपा ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया. लेकिन लखनऊ में उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट अब भी अधूरा है. अटल जी लखनऊ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन को अतिव्यस्त चारबाग स्टेशन के पर्याय के रूप में विकसित करना चाहते थे. चूंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेई लखनऊ से ही सांसद भी थे. जैसी कि परंपरा रही है और आज यह सर्वज्ञात भी है कि रेलवे की नौकरशाही सरकार की चापलूसी में बहुत माहिर है. इसी के चलते वर्ष 2000 में गोमती नगर में एक बड़े रेलवे टर्मिनस के विकास और निर्माण की योजना रेलवे द्वारा बनाई गई थी. हालांकि इसके नाम पर अब तक काफी पैसा रेल अधिकारियों ने बरबाद किया है, परंतु इसका काम आज भी पूरा नहीं हो पाया है. वर्ष 2004 में एनडीए की सत्ता जाने के साथ ही इसके विकास की गति रुक गई थी. अब एक बार फिर एनडीए सत्ता में है, तो गोमती नगर स्टेशन के बजाय वाराणसी स्टेशन पर रेलवे की चापलूस नौकरशाही ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि वहां से सांसद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

उल्लेखनीय है कि गोमती नगर टर्मिनस का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेई ने तत्कालीन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री, तत्कालीन रेलमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री मायावती और आवास एवं नगर विकास मंत्री लालजी टंडन की उपस्थिति में 21 मई 2000 को किया था. तब से इसका प्रयोग हॉल्ट के रूप में किया जाने लगा. रेलवे की अत्यंत खुदगर्ज और मौकापरस्त नौकरशाही ने करीब 13 साल बाद 18 दिसंबर 2015 को गोमती नगर को रेलवे स्टेशन का दर्जा तब दिया है, जब केंद्र में पुनः भाजपा नीत सरकार सत्ता में है. श्री बाजपेई के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वर्ष 2003 में एक उच्च स्तरीय समिति ने गोमती नगर को लखनऊ का दूसरा रेलवे टर्मिनस बनाए जाने की संस्तुति की थी. इसके लिए तब 96 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे. तब से लेकर अब तक इस प्रोजेक्ट पर सैकड़ों करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए गए हैं, परंतु खर्च के हिसाब से यहां कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है, जबकि इसकी बिना पर पूर्वोत्तर रेलवे के तत्कालीन जीएम का गोमतीनगर में बहुत भव्य बंगला अवश्य बन गया था.

वड़ोदरा मंडल के स्टेशनों का नाम उर्दू में लिखे जाने का भारी विरोध...

पेज 1 का शेष... की जनसंख्या ज्यादा होने के नाम पर सरकार की नीति बदलती है, तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका यह भी कहना है कि इस देश में 85 प्रतिशत जनसंख्या बहुसंख्यकों की है, तो सरकार द्वारा पिछले 68 सालों में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया?

इस बारे में संपर्क किए जाने पर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शरत चंद्रायन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वड़ोदरा मंडल के चार जिलों के 66 रेलवे स्टेशनों के नाम उर्दू में लिखे गए हैं. तथापि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस बारे में रेलवे बोर्ड ने भी ऐसा कोई निर्देश/आदेश जारी किया है या नहीं. क्योंकि भाषावार राज्यों की स्थापना के अनुसार रेलवे की यह नीति रही है कि सम्बंधित राज्य की स्थानीय भाषा (जैसे गुजरात के मामले में 'गुजरती') और एक राष्ट्रीय भाषा (हिंदी) तथा एक अंतरराष्ट्रीय भाषा (अंग्रेजी) यानि सिर्फ तीन भाषाओं में ही रेलवे स्टेशनों के नाम लिखे जाएंगे. तब गुजरात में सिर्फ चार जिलों के रेलवे स्टेशनों के लिए रेल मंत्रालय की इस भाषा नीति में बदलाव कैसे किया जा सकता है?

इसके अलावा क्या राज्य सरकार के निर्देश पर किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम उसकी मर्जी के अनुसार लिखा जा सकता है? यदि ऐसा है भी, तो रेलवे की अपनी एक विशिष्ट पहचान कहां रह जाएगी? जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है. राज्य सरकार को यदि रेलवे में किसी प्रकार का बदलाव करना है, तो सर्वप्रथम उसका प्रस्ताव उसे रेल मंत्रालय को भेजना होता है. रेल मंत्रालय द्वारा उसकी मंजूरी के बाद और उसके द्वारा ही जारी निर्देश के तहत उक्त कार्य संभव हो सकता है. इस मामले में ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, बल्कि राज्य के स्थानीय राजनीतिज्ञों की मिलीभगत या वोट की घटिया राजनीति के चलते वड़ोदरा मंडल के अधिकारियों ने दबाव में यह काम किया है. स्थानीय रहिवासियों द्वारा देश और समाज को बांटने वाली सरकार अथवा रेल मंत्रालय की इस तुगलकी नीति का पुरजोर विरोध किया जा रहा है. गुजरात की अधिसंख्य जनता ने कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम उर्दू में लिखे जाने का पुरजोर विरोध किया है.

नहीं हो पाई समय पर मेंबर इलेक्ट्रिकल की नियुक्ति...

पेज 1 का शेष... (सीपीओ/उ.रे.) के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था. जबकि मेंबर स्टाफ को मेंबर इलेक्ट्रिकल का अतिरिक्त चार्ज सौंपकर रेलवे बोर्ड ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है. मगर रेलवे बोर्ड में बैठे बड़े बाबू लोगों को अपने-अपने कैडर को फेवर करने तथा बड़े मंत्री महोदय को यात्रियों को खाना और दूध पहुंचाने की प्रचार लोलुपता तथा छोटे मंत्री महोदय को निहित ट्रांसफर/पोस्टिंग करने और विगत काफी समय से भारतीय रेल के अंडर इंवेस्टमेंट में रहने तथा अगले चार सालों में आठ लाख करोड़ का निवेश किए जाने की हर मंच पर रट लगाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है. ऐसे में पूर्व निर्धारित समय पर किसी बोर्ड मेंबर अथवा जोनल जीएम की नियुक्ति कैसे संभव हो सकती है? उल्लेखनीय है कि डीजी/एनएआईआर की पोस्ट 30 सितंबर से खाली पड़ी है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जीएम की पोस्ट को भी खाली होकर करीब 18-20 दिन हो गए हैं.

जबकि मेंबर ट्रैफिक की पोस्ट पर कुंदन सिन्हा के रहते सामान्य रूप से कामकाज चल ही रहा था, मगर उस पर श्री सिन्हा को बदलने की रेलमंत्री को बहुत ज्यादा जल्दी थी. यह जल्दी किसलिए थी, यह तो फिलहाल नहीं पता चल पाया है, मगर यह जल्दी तो थी. इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि किसी ओपन लाइन जीएम के पद पर कम से कम तीन महीने का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद ही ऐसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को बोर्ड मेंबर बनाए जाने की इस निर्धारित न्यूनतम अवधि को घटा दिए जाने का नोट रेलवे बोर्ड की तरफ से पीएमओ को न सिर्फ भेजा गया, बल्कि उसका पीछा करके और यह अवधि कम करवाकर मेंबर ट्रैफिक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे कुंदन सिन्हा को दरकिनार करके मोहम्मद जमशेद को उस पर ले आया गया. जानकारों का मानना है कि हालांकि मोहम्मद जमशेद की ईमानदारी और विश्वसनीयता किसी भी संदेह से परे है, और उन्हें मेंबर बनने की भी कोई जल्दबाजी नहीं थी, मगर ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय के वर्तमान निजाम को इस माध्यम से अपना कोई राजनीतिक हितसाधन करना है. रेलवे बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मोहम्मद जमशेद को तो वैसे ही 31 जनवरी को मेंबर ट्रैफिक बन जाना था, क्योंकि उनके अलावा इस पद के लिए रेलवे बोर्ड के पास अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं था. ऐसे में कुंदन सिन्हा को अतिरिक्त चार्ज से असमय हटाकर उनकी बेइज्जती क्यों की गई? जबकि उनसे पहले तत्कालीन एडीशनल मेंबर, कमर्शियल अजय शुक्ला को मात्र छह महीने के लिए ही इसी रेल प्रशासन ने मेंबर ट्रैफिक का अतिरिक्त चार्ज सौंपा था. उनका कहना है कि जब श्री शुक्ला को उनका कार्यकाल पूरा कर लेने दिया गया था, तब कुंदन सिन्हा के मात्र डेढ़ महीने और उक्त पद पर रह जाने से रेलवे बोर्ड अथवा भारतीय रेल का क्या बिगड़ जाता? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन में नैतिकता और शुचिता का ढिंढोरा पीटने वाले क्या इस तरह से वरिष्ठ, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को अपमानित नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि रेल मंत्रालय का वर्तमान निजाम भी पहले से अलग नहीं है.

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मेंबर इलेक्ट्रिकल बनने के लिए रेलवे बोर्ड के पास सिर्फ तीन वरिष्ठ अधिकारी ही उपलब्ध हैं. यह डीजी/आरडीएसओ, जीएम/ मेट्रो रेलवे, कोलकाता और जीएम/ आरसीएफ, कपुरथला हैं. इनमें से डीजी/आरडीएसओ को वर्तमान पद पर करीब दो साल से ज्यादा हो गए हैं, तथापि उनका कार्यकाल अभी 14 महीने बाकी है. जबकि जीएम/मेट्रो रेलवे को 26 अगस्त 2015 को जीएम बनाया गया था, उनका चार महीने से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जबकि उनकी सेवानिवृत्ति के भी 14 महीने ही बाकी हैं. जीएम/आरसीएफ 21 अक्टूबर को जीएम बने हैं. उन्हें जीएम बने अभी लगभग ढ़ाई महीने हो रहे हैं. अतः उन्हें इस रेस में नहीं माना जा रहा है. हालांकि उनका कार्यकाल अभी 15 महीने है. उपरोक्त स्थितियों के मद्देनजर मेंबर इलेक्ट्रिकल का चयन अथवा नियुक्ति डीजी/आरडीएसओ और जीएम/मेट्रो रेलवे में से किसी एक की ही की जानी है. जानकारों का मानना है कि ऐसे में उपयुक्त अधिकारी को अगला मेंबर इलेक्ट्रिकल बनाए जाने पर ही अगले चार सालों में 10 हजार किलोमीटर ट्रैक के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.

नई दिल्ली स्टेशन पर हेडऑन जनरेशन विद्युत इंजन लगी पहली ट्रेन 12952 दिल्ली-मुंबई राजधानी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु. उनके साथ हैं मेंबर स्टाफ प्रदीप कुमार, मेंबर मैकेनिकल हेमंत कुमार, मेंबर इलेक्ट्रिकल नवीन टंडन (31 दिसंबर को सेवानिवृत्त), महाप्रबंधक/उ.रे. ए. के. पुठिया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन.

लंबे समय से संवेदनशील पदों...

पेज 1 का शेष... नोटिफिकेशन इसी की पुनरावृत्ति के रूप में जारी किया गया है. जबकि सच यह है कि उपरोक्त तमाम संवेदनशील पदों पर 20-25 साल से भी ज्यादा समय से सैकड़ों-हजारों कर्मचारी लगातार पदस्थ हैं. स्थिति यह है कि ऐसे कर्मचारियों द्वारा न तो कभी अपनी छुट्टी ली जाती है और न ही वह कोई राष्ट्रीय छुट्टी मनाते हैं. परिणामस्वरूप इनके नीचे न तो कोई सेकेंड लाइन तैयार हो पाई है और न ही किसी अन्य मातहत कर्मचारी को इनका काम करने या सीखने का मौका मिल पाया है. इस वजह से जोनल रेलों को इन कर्मचारियों को इनके पदों से हटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

उदाहरण स्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे इसके लिए सबसे ज्यादा बदनाम रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड के उपरोक्त नोटिफिकेशन के परिप्रेक्ष्य में हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे के ऐसे करीब 40 कर्मचारियों को उनके पदों से अन्यत्र ट्रांसफर किया गया था, जो कि 20-25 और 28 सालों से लगातार संवेदनशील पदों पर ही पदस्थ हैं. परंतु इनमें से अब तक सिर्फ दो-चार कर्मचारियों को ही पदमुक्त किया जा सका है. बाकी कर्मचारियों को अब तक इसलिए पदमुक्त करके अन्यत्र नहीं भेजा जा सका है, क्योंकि उनका काम करना किसी अन्य कर्मचारी को नहीं आता है. हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यह एक बहाना है, क्योंकि ऐसा कोई भी कर्मचारी अपने वर्तमान पद को छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे उस पद पर प्रतिदिन की हजारों रुपए की अवैध कमाई का लालच है.

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक चार वर्ष पर सभी कर्मचारियों को और प्रत्येक तीन वर्ष पर सभी अधिकारियों को उनके पदों से दर-बदर किए जाने की बहुत पुरानी सरकारी पालिसी रही है. यदि रेलवे में इसके हजारों कर्मचारी 15-20-25 सालों से एक ही जगह एक ही पद पर और हजारों अधिकारी एक ही रेलवे एवं एक ही शहर में जमे हुए हैं, तो यह रेल प्रशासन की बहुत बड़ी और अक्षम्य लापरवाही कही जाएगी. यही वजह है कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को रेलवे बोर्ड सहित सभी रेलों/शहरों और सभी आवश्यक पदों पर काम करने तथा काम सीखने का मौका नहीं मिल पा रहा है. इसके अलावा रेलवे में नीचे से लेकर ऊपर तक व्याप्त भारी भ्रष्टाचार का भी यही सबसे बड़ा कारण है. इसके लिए सबसे पहले रेलवे बोर्ड को अपनी 'मुंहदेखी' नीति बदलने की आवश्यकता भी है.

अमूल्य जान बचाने हेतु महाप्रबंधक के हाथों मोटरमैन पुरस्कृत

कोलकाता : कवी सुभाष स्टेशन से दमदम के लिए 14 दिसंबर को गाड़ी (केडी-99) लेकर निकले मेट्रो रेलवे, कोलकाता के मोटरमैन एस. के. बंद्योपाध्याय को सुरंग में एक महिला पटरी पर चलती गाड़ी की ओर आते दिखाई दी. उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि उक्त महिला आत्महत्या करने के इरादे से आ रही है. उन्होंने तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को जगह पर ही रोक लिया. इससे उक्त महिला की कीमती जान जाते-जाते बच गई. इस सराहनीय कार्य और मेट्रो सुरंग में आत्महत्या करने निकली महिला की अमूल्य जान बचाने के लिए महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे ए. के. कपूर ने 31 दिसंबर को मेट्रो रेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मोटरमैन श्री बंद्योपाध्याय को पुरस्कृत किया.

जीवन और राष्ट्र निर्माण में नैतिकता की प्रमुख भूमिका होती है –राजीव मिश्र

■ एन. ई. रेलवे बालक-बालिका इंटर कालेज का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न

एन. ई. रेलवे बालिका इंटर कालेज, गोरखपुर के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र.

गोरखपुर ब्यूरो : एन. ई. रेलवे बालिका इंटर कालेज, गोरखपुर का 87वां वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 23 दिसंबर को विद्यालय प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ. समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रीमती कुमकुम मिश्र ने विद्यालय के सर्वोत्तम छात्रा, खेल-कूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया. इसके पूर्व महाप्रबंधक श्री मिश्र ने विद्यालय की छात्राओं द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया. इस अवसर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी एस.एन.एम. इस्लाम, मुख्य संरक्षा अधिकारी एन. के. अम्बिकेश, पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की सचिव श्रीमती कविता सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों, सदस्याओं सहित वरिष्ठ रेल अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक एवं बच्चे उपस्थित थे. इससे एक दिन पहले 22 दिसंबर को एन. ई. रेलवे बालक इंटर कालेज का भी वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ.

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने अपने संबोधन में विज्ञान प्रदर्शनी को उत्कृष्ट बताते हुए छात्राओं की विज्ञान के प्रति विशेष रूचि की सराहना की. विद्यालय के शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने इसे और बेहतर बनाने तथा छात्राओं को नैतिक मूल्यों की शिक्षा के साथ स्वच्छता के प्रति भी जागरूक करने की सलाह भी शिक्षकों को दी. इस मौके पर प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की उत्कृष्टता की प्रशंसा करते हुए महाप्रबंधक ने इसे शिक्षकों एवं छात्राओं के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में सीखने की अपार क्षमता होती है. अतः शिक्षक उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें, जिससे विद्यार्थियों में स्वभाविक रूप से अच्छे नागरिक के गुण विकसित हो सकें. श्री मिश्र ने कहा कि जीवन में नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व है तथा राष्ट्र निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका होती है. महाप्रबंधक ने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को विकसित करें तथा प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत' का नारा चरितार्थ करने में उनकी भूमिका का भी निर्धारण करें. उन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कार्यक्रम के आयोजन हेतु 20-20 हजार रुपए के सामूहिक पुरस्कारों की भी घोषणा की.

नव-वर्ष पर रेलकर्मियों/यात्रियों को महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे की शुभकामनाएं

गोरखपुर : महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे राजीव मिश्र ने पूर्वोत्तर रेलवे के अपने सभी रेलकर्मियों, अधिकारियों, रेल कर्मचारी यूनियनों, दैनिक रेल यात्रियों तथा समस्त रेल उपभोक्ताओं को उनके तथा उनके परिजनों को नव-वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं. महाप्रबंधक श्री मिश्र ने नव-वर्ष के अवसर पर रेलकर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ्य, सफल एवं सुखमय जीवन की कामना की है. उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नए वर्ष में सभी रेलकर्मी और अधिकारीगण मिलकर सच्ची कर्तव्यनिष्ठा, मेहनत और लगन से रेलवे की प्रगति में भागीदार बनेंगे और रेलवे की छवि उज्ज्वल बनाने के लिए रेल यात्रियों का उचित मार्गदर्शन करेंगे.

राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाना हमारा दायित्व है –अरुण सक्सेना

उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक शैलेंद्र कपिल की कार्यकृति 'हमसफर के साथ' का विमोचन करते हुए महाप्रबंधक अरुण सक्सेना. उनके साथ हैं शैलेंद्र कपिल एवं अन्य अधिकारीगण.

उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक अरुण सक्सेना.

इलाहाबाद ब्यूरो : उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में महाप्रबंधक अरुण सक्सेना की अध्यक्षता में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक श्री सक्सेना ने कहा कि सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाना हमारा संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है. उन्होंने कहा कि उत्तर मध्य रेलवे में अन्य रेलों की तुलना में राजभाषा हिंदी का बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है, यह निःसंदेह सराहनीय है. श्री सक्सेना ने राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मदों की प्रगति के संदर्भ में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के सभी प्रलेखों में अनिवार्य रूप से हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी का प्रयोग बनाए रखने पर जोर दिया तथा इसकी प्रभावी निगरानी के आदेश भी दिए.

सूचना माध्यमों में हिंदी के प्रयोग हेतु सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट पर विभिन्न विभागों, मंडलों तथा कार्यालयों से संबंधित विषय सामग्री हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए तथा इन्हें निरंतर अपडेट किया जाना चाहिए. महाप्रबंधक ने सिगनल एवं दूरसंचार, बिजली, यांत्रिक आदि जैसे तकनीकी विभागों के परिचालन एवं अनुरक्षण संबंधी अनुदेशों आदि को शत-प्रतिशत हिंदी में जारी किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक डिक्टेशन हिंदी में दें तथा निरीक्षण रिपोर्ट हिंदी में ही जारी किया जाना सुनिश्चित करें. इस अवसर पर महाप्रबंधक ने उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'रेल संगम' के निर्माण संगठन विभाग विशेषांक का विमोचन किया.

बैठक के प्रारंभ में मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य बिजली इंजीनियर बी. के. सोनावने ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा उत्तर मध्य रेलवे में हुई राजभाषा प्रगति से समिति को अवगत कराया. श्री सोनावने ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के दो कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट रचनात्मक प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया है तथा इनमें से एक को सरकार की मौलिक पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा तथा दूसरे कर्मचारी को रेलमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है. बैठक में उपस्थित अपर महाप्रबंधक, सभी विभाग प्रमुखों, अपर मंडल रेल प्रबंधकों, मुख्य कारखाना प्रबंधकों ने अपने-अपने विभागों एवं मंडलों में राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में महाप्रबंधक को अवगत कराया.

इस अवसर पर 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी बी. के. सोनावने का राजभाषा प्रसार के लिए किए गए उनके विशिष्ट योगदान के लिए अभिनंदन किया गया तथा नवनियुक्त मुख्य राजभाषा अधिकारी के रूप में मुख्य कार्मिक अधिकारी ओम प्रकाश का स्वागत किया गया. बैठक में महाप्रबंधक ने मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक शैलेन्द्र कपिल की हाल ही में प्रकाशित कार्यकृति 'हमसफर के साथ' का भी विमोचन किया. शैलेन्द्र कपिल ने कृति की विषयवस्तु और उसके रचनात्मकता पर प्रकाश डालते हुए कविता पाठ भी किया. बैठक का संचालन चन्द्रभूषण पांडेय, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी द्वारा ने किया तथा उप मुख्य राजभाषा अधिकारी विनीत द्विवेदी ने धन्यवाद ज्ञापित किया.

अजीवन सदस्यता 3000 रु., संरक्षक सदस्यता 5000 रु., कृपया चेक/डीडी 'सोहम पब्लिकेशन' के नाम निम्नलिखित संपादकीय कार्यालय के पते पर भेजें.

परिपूर्ण रेलवे समाचार

संपादकीय कार्यालय
रूम नं. 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र)
मोबाइल नं. : 9869256875

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुरेश त्रिपाठी द्वारा सोहम पब्लिकेशन, 105, डॉक्टर हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जि. ठाणे. (महाराष्ट्र) से मुद्रित एवं 105, डॉक्टर्स हाउस, पहला माला, रहेजा कॉम्प्लेक्स, पथरी पुल के पास, कल्याण (पश्चिम)-421301. जिला- ठाणे. (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.

संपादक – सुरेश त्रिपाठी

- इलाहाबाद : उमेश शर्मा ☎ 094155 08625
- गोरखपुर : विजय शंकर ☎ 09935266331
- भुसावल : शेख सत्तार ☎ 093706 15244
- रतलाम : मुकेश सिंह ☎ 094274 84069
- वड़ोदरा : विजय नायर ☎ 098240 16464

कानूनी सलाहकार
* एड. एम. एस. ठक्कर, कल्याण,
* एड. प्रकाश ताहिलरामानी, मुंबई,
* एड. राजेश मुधोलकर, ठाणे,
* एड. कमलेश त्रिपाठी, रायबरेली,
* एड. बी. एच. वास्वानी, भोपाल,
* एड. एम. पी. दीक्षित, पटना.

किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का न्यायिक क्षेत्र कल्याण होगा.

RNI Regd. No. MAHHIN/2002/10618
POST Regd. No. Tech/47-1542/MBI/2015-2017